ईरान और पी5+1 के बीच परमाणु वार्ता: अपनी-अपनी सुरक्षित सीमा

*डॉ. आसिफ शुजा**

ईरान और पी5+1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों व जर्मनी के बीच परमाणु वार्ता तेजी से एक सहमत समय-सीमा और स्वीकार्य प्रारूप की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। मार्च, 2015 में ईरान और अमरीका के बीच अब तक की गई बातचीत से प्रगति के उत्साहवर्धक संकेत मिले हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी अपने समकक्ष ईरान के विदेश मंत्री जावाद जारिफ के साथ की गई इन वार्ताओं के बारे में सकारात्मक प्रतीत हुए और उन्होंने तदनुसार पी5+1 के अन्य सदस्यों, विशेषकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को (इसके बारे में) जानकारी दी है। दोनों दल एक व्यापक समझौते पर पहुंचने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए समय सीमा जुलाई 2015 निर्धारित की गई है।

ईरान के परमाणु वार्ताओं की सकारात्मक दिशा ने इज़राइल के मन में व्याकुलता पैदा कर दी है, जैसा कि 3 मार्च, 2015 को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र पर इसके (इज़राइल के) प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिए गए भाषण से स्पष्ट है। नेतन्याहू ने यह कहते हुए लंबित समझौते की संभावित शर्तों पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की कि वैश्विक ताकतें (वे परोक्ष रूप से अमरीका को संदर्भित कर रहे थे) एक गलत समझौता करने की ओर बढ़ रही हैं और सुझाव दिया कि कोई भी समझौता न करना एक गलत समझौते से बेहतर होता। नेतन्याहू की चिंताओं की प्रतिक्रिया में, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोहराया कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करने के बावजूद, नेतन्याहू इस समस्या को हल करने के लिए कोई भी वैकल्पिक विकल्प सुझाने में विफल रहे हैं। वास्तव में, नेतन्याहू का भाषण यह दर्शाने के साथ-साथ कि ईरान परमाणु समझौता उत्तरोत्तर एक वास्तविकता बनता जा रहा है, उनके घरेलू निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने और इज़राईल में 17 मार्च 2015 को होने वाले चुनावों में लाभ लेने के लिए अधिक था।

आसन्न ईरान परमाणु समझौते ने न केवल इज़राइल को प्रभावित किया है, बल्कि इसकी परिणति ने स्वयं कांग्रेसियों को भी चिंता में डाल दिया है, जोकि अयातुल्लाह खुमैनी को लिखे एक खुले पत्र से स्पष्ट है, जिसे यह धमकी देते हुए 47 रिपब्लिकन सीनेटरों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था कि ईरान और अमरीका के राष्ट्रपति के बीच किए गए किसी भी समझौते का तब तक कोई कानूनी स्वरूप/आधार नहीं होगा जब तक कि यह कांग्रेस द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो; जो उत्तरोत्तर इस परमाणु समझौते को पटरी से उतरने की कोशिश है। इस पहल की पूर्ण भर्त्सना करते हुए, ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद जावाद जारिफ ने इन सीनेटरों को अपना संविधान पढ़ने के लिए कहा।

दरअसल, इस पहल ने अपने ही घर के मतभेद उजागर करते हुए इस समझौते पर अमरीका की स्थिति बेहतर करने से कहीं अधिक उसे नुकसान पहुंचाया है। वास्तव में, इस कार्रवाई का समर्थन करने वाले कांग्रेसियों की संख्या बढ़कर अब 367 हो गई है, जो ईरान परमाणु समझौते पर बढ़ते आंतरिक विरोध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

स्पष्टत:, ईरान और पी5+1 के बीच संयुक्त कार्य-योजना में परिकल्पित तथा 24 नवंबर, 2013 को सहमत इस परमाणु समझौते का अंतिम लक्ष्य ईरान के इस आश्वासन - कि इसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है - के बदले ईरान को यूरेनियम संवर्धन का वैध अधिकार प्रदान करना और इस देश पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना है। संबंधित पक्षकारों द्वारा अपनी-अपनी सुरक्षित सीमा तय करने में आ रही कठिनाई के कारण इस संकट का कोई दीर्घकालिक समाधान अवरूद्ध है। वास्तव में, दोनों पक्षकार कम से कम अपने न्यूनतम सौदेबाजी तक पहुंचने के लिए अपनी-अपनी सुरक्षित सीमा पर दृढ़ रूप से कायम और अपने-अपने राष्ट्रवादी घरेलू मतदाता वर्गों को रिझाते प्रतीत होते हैं।

ईरान के लिए सुरक्षित सीमा का अर्थ है कि यह परमाणु तकनीक से ऊर्जा उत्पादन अथवा चिकित्सा प्रयोजनों जैसे शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। ईरान ने अपने देश से सभी प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव किया है ताकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से आसानी से जुड़ सके और विश्व बाजार में अपने तेल निर्बाध रूप से खुलकर बेच सके। ईरान इस मांग पर समझौता करने का इच्छुक नहीं है। दूसरी ओर, पी5+1 के लिए और विशेष रूप से अमरीका के लिए अनुमानित सुरक्षित सीमा यह है कि यदि ईरान चाहे तो भी उसे किसी परमाणु हथियार का उत्पादन करने में सफल हो पाने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय लगे। ऐसी भी सूचना है कि वे (पी5+1) ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि यह यथास्थिति लगभग एक और दशक तक बनी रहे।

विशेष रूप से, पश्चिमी ताकतें ईरान में संचालित किए जाने वाले अपकेंद्रों (सेंट्रीफ्यूज) की संख्या सीमित करना चाहती हैं ताकि यूरेनियम संवर्धन की इसकी क्षमता सीमित की जा सके। इसके अतिरिक्त, वे ईरान की धरती से मौजूदा संवर्धित युरेनियम को या तो नष्ट करके या उन्हें समुद्री रास्ते से ईरान से निकालकर, संभवतः रूस के पास भेजकर, हटाना चाहते हैं, जिसपर अतीत में सहमति हो गई थी। ईरान की धरती पर अपकेंद्रों (सेंट्रीफ्यूज) की संख्या और संवर्धित युरेनियम की मात्रा इस तरीके से तय की जानी है कि यदि ईरान इस करार को तोड़ देता है तो उसे किसी परमाणु हथियार का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त संवर्धित युरेनियम का उत्पादन करने में एक वर्ष से कम समय न लगे। ऐसी भी सूचना है कि इस करार की शर्तों में इस यथास्थिति को कम से कम एक दशक के लिए कायम रखना शामिल किया जा सकता है।

20 जनवरी, 2014 को संयुक्त कार्य-योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय, ईरान लगभग 10,000 अपकेंद्रों (सेंट्रीफ्यूज) को चला रहा था और अमरीका तथा अन्य पश्चिमी ताकतें स्पष्ट तौर पर इसे कम करके 6,000-7,000 की सीमा तक लाने के लिए वार्ताएं कर रही हैं। इस समझौते का एक अन्य मुद्दा यह है कि ईरान 5 प्रतिशत से अधिक यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। इसके पास कथित तौर पर अपने दो परमाणु संवर्धन संयंत्रों, नतांज और फोर्डो में लगभग 19,000 अपकेंद्र (सेंट्रीफ्यूज) हैं। इस करार को पक्का करने में आने वाली प्राथमिक कठिनाई यह पता लगाना है कि ईरान को वाकई कितने अपकेंद्र (सेंट्रीफ्यूज) संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए विशेषकर इसलिए कि सभी अपकेंद्र (सेंट्रीफ्यूज) एक ही प्रकार के नहीं हैं। कुछ प्रकार के अपकेंद्रों (सेंट्रीफ्यूज) की संवर्धन क्षमता कम है जबकि कुछ उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी ज्यादा तेज संवर्धन क्षमता सुनिश्चित करते हैं। अपकेंद्र (सेंट्रीफ्यूज) की उस सही संख्या और प्रकार की गणना करना, जो किसी बम के निर्माण हेतु पर्याप्त युरेनियम का संवर्धन कर पाने में सफलता प्राप्त करने लिए एक वर्ष की अवधि सुनिश्चित कर सके, एक कठिन कार्य है और यह लंबी वार्ताओं के कारणों में से एक (प्रमुख) कारण है।

हालांकि, इस समझौते की परिणति को बाधित करने वाला एक और गंभीर मुद्दा (मौजूद) है और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रक्रिया में ईरान की भूमिका की संकल्पना और इसके (ईरान के) आईसोलेशन को समाप्त करने में इसकी बड़ी भूमिका है। इस्लामिक राष्ट्र (आईएस) के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय उथल-पुथल से प्रभावित पश्चिमी एशियाई क्षेत्र की मौजूदा भू-राजनीति ने पश्चिमी ताकतों को (आईएस) के विरूद्ध (किए जाने वाले) किसी भी जवाबी हमले में ईरान को शामिल करने पर मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब द्वारा यमन में हाउती विद्रोहियों पर हाल के हवाई हमले ने इस क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा कर दी हैं और

सऊदी अरब और ईरान के बीच सांप्रदायिक और क्षेत्रीय मतभेद और अधिक बढ़ सकते हैं यदि ईरान पश्चिमी ताकतों के इशारे पर पश्चिमी एशिया के भू राजनीतिक रंगमंच पर सक्रिय हो जाता है। इस करार के भू राजनीतिक लाभांश इसकी लघु आवधिक लागत से अधिक भारी (महत्वपूर्ण) समझे जा रहे हैं। इन जटिल विन्यासों को देखते हुए, ईरान का परमाणु करार पश्चिम को थोड़ी राहत देगा, ताकि वे आतंकवाद और इससे संबंधित मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे सकें।

कांग्रेसियों के खुले पत्र और इज़राइल के चुनाव में नेतन्याहू की जीत के बावजूद वार्ताओं का जारी रहना, ईरान के साथ करार पक्का करने की अमरीकी राष्ट्रपति की दृढ़ता को पर्याप्त रूप से दिखलाते हैं। इसी प्रकार, यमन में (जारी) वर्तमान सांप्रदायिक संघर्ष, जिसमें अब सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी के अनेक राष्ट्रों द्वारा सैन्य हस्तक्षेप भी किए जा रहे हैं, परमाणु वार्ता को किसी सकारात्मक परिणति तक ले जाने की आवश्यकता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब केवल कोई गंभीर अप्रिय घटना ही ईरान और अमरीका के नेतृत्व वाली पी5+1 के बीच की वार्ताओं को पटरी से उतार सकती है।

***

डॉ. आसिफ शुजा विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।